संख्या-132/2021/3031/26-3-2021

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 18 नवम्बर 2021

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में प्रथम किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-222/24/पी0ए0सी0/ज0जा0वि0/2021-22, दिनांक-13.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-02-796-01-0108 जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत निर्माण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0-2000.00 लाख के सापेक्ष जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित 05 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (छाउछ, चन्दन चौकी, बेलापरसुआ, जनपद-लखीमपुर-खीरी, विशुनपुर विश्राम, जनपद-बलरामपुर एवं नौतनवा जनपद-महराजगंज) में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित कराये जाने हेतु आगणित **धनराशि रू0 298.75 लाख (दो करोड़ अठ्ठान्वे लाख पचहत्तर हजार मात्र) की** प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1)-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(3) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(7) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(12) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(13) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

(14)-प्रश्नगत कार्यों में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12-05-2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15)-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0108-जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत निर्माण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वित्त ई-4-1865-दस/2021, दिनांक-16 नवम्बर, 2021 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृसं0-132/2021/3031(1)/26-3-2021 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

4- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी, महराजगंज एवं बलरामपुर।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

6- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।

8- निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।

9- गार्डफाइल

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।